The Draft Agriculture Policy Resolution seeks to provide policy framework for agricultural development at macro-level, to guide the formulation of specific sub-sectoral|sub-regional programmes. The Draft includes reference to horticulture and developing areas of untapped potential including hilly regions.

Self-sufficiency in Foodgrains

529. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all States are expected to attain self-sufficiency in foodgrains by the end of the Eighth Five Year Plan; and

(b) if so, the details thereof and the names of the States which would not attain self-sufficiency in foodgrains and the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) and (b) During the Eighth Five Year Plan it has been maintained that food security and relative self-sufficiency in food production is a strategically desirable long term goal for the country.

The strategy of agricultural development during the Eighth Five Year Plan aims at achieving self-sufficiency in foodgrains for the country as a whole and not on State-wise basis as self-sufficiency in foodgrains in all States may not provide optimal crop mix.

Joint venture for seed production

530. SHRI S. MADHVAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the American seed companies want to have joint ventures in India for seed productiin and export; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) and (b) Yes, Sir. After the announcement of New Industrial Policy, Department of Industrial Development have approved ies namely, M/s Agrigenetics USA, M/s Strayer Seed, USA and M/s Pioneer Overseas Corpn., USA for joint ventures with Indian companies for seed production in India.

गेहूं की खेती के लिए प्रयुक्त की जा रही भूमि

531. **श्री राम नरेश यादव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय, राज्यवार, कुल कितनी भूमि पर गेहूं की खेती की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान गेहूं के उत्पादन में कमी आई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने हेतु किसानों को ; प्रोत्साहन दिए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं तो, इस संबंध में किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1992–93 के दौरान गेहूं की खेती के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले संभावित क्षेत्रों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

("000 हैक्टेयर में)

बिहार . .	1950
गुजरात . .	486
हरियाणा . .	1900
हिमाचल प्रदेश .	370

जम्मू और कश्मीर	241
कर्नाटक	228
मध्य प्रदेश	3479
महाराष्ट्र	680
पंजाब	3236
राजस्थान	1978
उत्तर प्रदेश	8773
पश्चिम बंगाल	600
अन्य	292
समस्त भारत :	24213

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) देश में गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये 1988–89 से सात बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों यथा—बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम—गेहूं की एक केन्द्र क्षेत्रीय योजना चलायी जा रही है । 1992–93 के दौरान, उच्च पैदावार वाली किस्मों के प्रमाणीकृत बीजों सूक्ष्म पोषक तत्वों, खरपतवार नाशियों, पादक संरक्षक रसायनों, बीज उपचार रसायनों, बैल से खींचे जाने वाले अभिज्ञात उपस्करों तथा पादप संरक्षक उपस्करों के संवितरण पर प्रोत्साहन दिया गया । इसके अलावा, अपतृण नाशियों पर प्रदर्शन तथा किसानों के प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया । उपर्युक्त के अलावा, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र सहित सभी गेहूं उत्पादक राज्यों में गेहूं के मिनीकिट प्रदर्शन कार्यक्रम का भी क्रियान्वयन किया गया । इस योजना को 1993–94 के दौरान भी जारी रखे जाने की संभावना है ।

Seperate Funds for Natural Disasters

532. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether there is any separate fund allocated by Government to meet demands caused by natural disasters expeditiously;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether there is any permanent agency or organisation to administer the above funds in times of need and organise relief operations in the affected areas; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVND NETAM): (a) and (b) Based on the recommendations of the IX Finance Commission, a Calamity Relief Fund (CRF) with a separate identity, has been constituted for each State with specified amount for undertaking relief opertations in the wake of natural calamities. The contribution to the Fund with an annual corpus of Rs 804.00 crores is made by the Central Government and the State Governments in the ratio of 3:1. The Central share is released in four equal quarterly instalments.

(c) and (d) A State Level Committee headed by the Chief Secretary of the respective States, is fully empowered to decide on all matters relating to the financing of relief operations in the wake of natural calamities from out of CRF including norms of assistance.

कपास का उत्पादन

533. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व में कपास की खेती के लिए प्रयुक्त होने वाला भू-क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपास-उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान कपास का उत्पादन करने वाले देशों में चीन, अमरीका और रुस के बाद चौथा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विश्व में कपास-उत्पादन की दर की तुलना में भारत कपास-उत्पादन की दर लगभग आधी है ;